Volume - 14 (Issue - 9)

August, 2022

ISSN - 2230 - 9578

Journal of Research and Development

A Multidisciplinary International Level Refereed Journal

COSMOS
IMPACT FACTOR

7.26

Editor : Dr. R.V. Bhole

'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot No-23, Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102
Email - info@jrdrb.com   Visit - www.jrdrvb.com

	Jogdand, R.S. Shinge and S.D. Patil.		
49	सहा.प्रा. सुचित्रा किशोर लाउतकर	बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांचे सबळीकरण व समाजाचे सक्षमीकरण	186-191
50	प्राचार्य.डॉ.संजय शालकराव शिंदे श्री.महेंद्र साहेबराव पाटील	शाळासिद्धी :- प्रभावी गुणवत्ता व्यवस्थापन	192-195
51	प्रा. शामसिंग रामसिंग वळवी प्रा.डॉ. सुनिल अ. पाटील	आदिवासी भिल्ल जमातीतील स्त्रियांचे सामाजिक व आर्थिक जीवन	196-198
52	सुनिता संतोष पवार	भारत की नई शिक्षा नीति २०२०: एक सैद्धांतिक विश्लेषण	199-202
53	Prof.Dr. Dinesh Baban Deore Rohit Narayan Ature	Pan-Cancer molecular subtypes revealed by mass spectrometry based proteomic characterization of more than 500 human cancers	203
54	Prof.Dr. Dinesh Baban Deore Virendra Chatur Mali	Sperm DNA damage compromises embryo development but not oocyte fertilisation in pigs	204
55	ललितकुमार बारसागडे	राईट टु एज्युकेशन अंतर्गत मोफत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेतांना आव्हाने	205-209
56	परीक्षा सुरेश पाटील डॉ. संजय शिंदे	दैनिक वर्तमानपत्रांचे शिक्षणातील योगदान	210-216
57	प्रा.डॉ.मधुकर आत्माराम देसले कांचन भरतसिंग पाटील	नोकरी करणाऱ्या महिला शिक्षिकांच्या समस्या	217-220
58	प्रा.डॉ.मधुकर आत्माराम देसले राहुल साहेबराव जगदेव	नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषण एक सामाजिक समस्या	221-223
59	प्रा. डॉ. संजय जिभाऊ अहिरे नागेश श्रीकृष्ण शिंगणे	राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० यांचे तुलनात्मक परिक्षण	224-227
60	श्री. अमृत नामदेव पाटील	शिक्षणातून पर्यावरण संवर्धन व प्रदूषण निवारण	228-232
61	किशोर संतोष पाटील	ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थिनींच्या दृष्टिकोनातून विविध क्षेत्रातील लैंगिक असमानता एक अभ्यास	233-236
62	श्रीमती. कामिनी रामदास पवार	प्रायोगिक संशोधन पध्दती	237-240

भारत की नई शिक्षा नीति २०२०: एक सैद्धांतिक विश्लेषण

सुनिता संतोष पवार (सहायक प्राध्यापक,समाजशास्त्र विभाग)
कला व वाणिज्यमहाविद्यालय अक्कलकुवा, नंदुरबार,महाराष्ट्र

• सार -

अच्छी तरह से परिभाषित और भविष्य की शिक्षा नीति स्कूल और कॉलेज स्तरों पर एक देश के लिए आवश्यक है क्योंकि इस कारण से कि शिक्षा आर्थिक और सामाजिक प्रगति की ओर ले जाती है। विभिन्न देश परंपरा और संस्कृति पर विचार करके विभिन्न शिक्षा प्रणालियों को अपनाते हैं और इसे प्रभावी बनाने के लिए स्कूल और कॉलेज शिक्षा स्तरों पर अपने जीवन चक्र के दौरान विभिन्न चरणों को अपनाते हैं।

हाल ही में भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति की घोषणा डॉ. कस्तूरीरंगन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) क पूर्व अध्यक्षकी अध्यक्षता में की गई। यह पत्र उच्च शिक्षा प्रणाली में घोषित विभिन्न नीतियों पर प्रकाश डालता है और वर्तमान में अपनाई गई प्रणाली के साथ उनकी तुलना करता है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली पर एनईपी २०२० के विभिन्न नवाचारों और अनुमानित प्रभावों के साथ-साथ इसकगुणों पर चर्चा की गई है।अंत में, इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में इसकप्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ सुझाव प्रस्तावित हैं।

मूल शब्द - राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०, ज्ञान, शिक्षा.

• प्रस्तावना -

किसी भी देश के विकास के लिए वहां के नागरिकों की शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। यदि शिक्षा का स्तर मजबूत होगा तो वहां का देश तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर होगा। हमारे देश में शिक्षा नीति पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है इसलिए भारत अभी भी विकासशील देश बना हुआ है। भारत में पहली बार शिक्षा नीति१९८६ में बनाई गई थी वर्ष१९९२ में संशोधन किया गया। शिक्षा नीतियो में कमी देश की विकास में बाधा बनी। नई शिक्षा नीति२०२० प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई जो कि पुरानी शिक्षा नीति से ज्यादा अच्छी और असरदार नजर आती है। किसी भी देश की बुनियादी आवश्यकता शिक्षा नीति है, क्योंकि उससे देश के अतीत का विश्लेषण,वर्तमान की आवश्यकता व भविष्य की संभावनाएं निहित होती है। जीवन में शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नए परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति२०२० को मंजूरी दी ।

नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत करते हुए शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ने कहा -देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात कही है- जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में यह नई शिक्षा नीति२०२० मील का पत्थर साबित होगी।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० -

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दी गई है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत देश की जीडीपी के६% कबराबर केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति ५+३+३+४ पैटर्न पर आधारित है।

• शिक्षा नीति की विकास यात्रा -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति१९६८

- भारत में पहली शिक्षा नीति कोठारी आयोग(१९६४-१९६६) की सिफारिशों पर आधारित थी ।
- १४ वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य लक्ष्य रखा गया।
- प्राचीन संस्कृत भाषा कशिक्षण को प्रोत्साहित किया ।
- केंद्रीय बजट का६% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया।

- त्रिभाषा सूत्र माध्यमिक स्तर पर लागू किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६

- शिक्षा नीति का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
- प्राथमिक शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड लांच किया गया।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का विस्तार किया गया।
- ग्रामीण भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण विश्व विद्यालय मॉडल की नीति का आह्वान किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन १९९२

- शिक्षा नीति में संशोधन का उद्देश्य पूरे देश में व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षण में प्रवेश कलिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था।
- राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE)निर्धारित की।

शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों?

- शिक्षण प्रणाली में वर्तमान में वैश्वीकरण के बदलते परिदृश्य में ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षण को दर्जेदार बनाने क लिए और नए विचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने क लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- शिक्षा कवैश्विक मानकों को अपनाने कलिए भी शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

नई शिक्षा नीति२०२० के उद्देश्य

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति२०२० का लक्ष्य वर्ष२०३० तक सकल नामांकन अनुपात१००% करना।
- पांचवी कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करवाना ।
- मातृभाषा को कक्षा८और उससे आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- इस नीति कतहत३ से१८ वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून२००९ के अंतर्गत रखा गया है।
- न्यू एजुक्शन पॉलिसी२०२० का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है।
- २०२५ तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा(६ वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना।
- इसकेअंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के६% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
- देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद' नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई।

नई शिक्षा नीति२०२० के तहत२०३० तक शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया गया है और वर्तमान में चल रही १० + २ के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में ५ + ३ + ३ + ४ की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति२०२० कलिए केंद्र तथा राज्य सरकार के निवेश का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए देश की६% जीडीपी के बराबर शिक्षा क्षेत्र में निवेश करेगी।

- नई शिक्षा नीति के चरण -

शिक्षा नीति के चरणों नई को४ चरणों में विभाजित किया गया है।फाउंडेशन स्टेज :-इस स्टेज में३ से८ साल के बच्चों को शामिल किया गया है जिसमें छात्रों का भाषा कौशल और शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रीपेटरी स्टेज :- प्रीपेटरी स्टेज में ८ से११ साल के बच्चों को शामिल किया गया है,यह बच्चे कक्षा३ से५ तक के होंगे इस चरण में बच्चों का संख्यात्मक कौशल्य को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं काज्ञान दिया जाएगा

मिडिल स्टेज :- मिडिल स्टेज में कक्षा छठवीं से आठवीं कबच्चे होंगे बच्चों को छठवीं कक्षा से कोडिंग सिखाया जाएगा इन बच्चों को व्यवसायिक परीक्षण के साथ-साथ व्यवस्था इंटरशिप के अवसर दिए जाएंगे

सेकेंडरी स्टेज :- सेकेंडरी स्टेज में कक्षा बारहवीं के छात्रों को शामिल किया जाएगा इसमें बारहवीं कक्षा के शैक्षणिक पाठ्यक्रम को समाप्त करके बहुविकल्पीय शैक्षिक पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी इसमें छात्र अपनी मनपसंद कअनुसार विषय का चुनाव कर सकते हैं बच्चों को विषयों के चुनाव की स्वतंत्रता दी गई है छात्र साइंस के विषयों के साथ साथ आर्ट्स कॉमर्स के विषय का अध्ययन कर सकते हैं

- नई शिक्षा नीति२०२२ के लाभ -

  नई शिक्षा नीति में प्राचीन भाषाओं के साथ-साथ विदेशी भाषा पढ़ने का विकल्प रखा गया है
- १० th सीबीएसई बोर्ड तथा राज्य सरकार वाली प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।
- शिक्षा को आसान बनाने के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया जाएगा।
- छात्र को न्यूनतम३ भाषाओं का ज्ञान होगा।
- नई शिक्षा नीति में छात्रों को प्रशिक्षण एवं अनुसंधान करने के लिए लैब प्रदान की जाएंगी।
- Higher Education MPhil Degree खत्म किया जा रहा है।
- छात्रों को पढ़ाई के साथ प्रशिक्षण पर विशेष रुप से ध्यान दिया जाएगा।

New Education Policy २०२० के तहत छात्र कोई भी कोर्स बीच में छोड़कर किसी अन्य कोर्स में दाखिला लेना चाहता है तो वह एक निश्चित समय के पश्चात दूसरे कोर्स में दाखिला ले सकता है।

भारत की नई शिक्षा२०२० नीति के मुख्य बिंदू

- अनुसंधान और नवाचार केंद्रित:
- HE पाठ्यक्रम के बेहतर STEM मॉडल:
- छात्र केंद्रित मॉडल:
- योग्यता आधारित सतत मूल्यांकन प्रणाली:
- अनुसंधान आउटपुट पर आधारित संकाय उत्पादकता:
- सभी स्तरों पर स्वायत्तता:
- मेरिट आधारित छात्र प्रवेश, संकाय चयन और पदोन्नति
- शिक्षा के नेताओं को रोल-मॉडल होना चाहिए:
- एकीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली
- सुधार के लिए आगे के सुझाव :

  पीएच.डी. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक स्थायी शिक्षण स्थिति के लिए एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए
- अनिवार्य संकाय वार्षिक प्रकाशन आईपीआर के लिए अग्रणी
- अनुसंधान मार्गदर्शिकाओं के रूप में सेवानिवृत्त प्रोफेसरों की सेवाओं का उपयोग
- Multidisciplinary College की एक उचित परिभाषा
- उच्च शिक्षा नेताओं को अनुसंधान और नवाचारों में रोल मॉडल होना चाहिए
- HEIs में शिक्षण-सीखने की प्रक्रियाओं के अनिवार्य तीन तरीके:
- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के दौरान अनिवार्य प्रकाशन / पेटेंट:
- विश्वविद्यालयों के पास अपनी स्वयं की प्रकाशन इकाई होनी चाहिए ।

  लेखकों के साथ कॉपीराइट केप्रतिधारण के साथ ओपन एक्सेस पब्लिकेशन के लिए प्रचार:

एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (INDL) को मजबूत करना।

- **नई शिक्षा नीति के मार्ग की चुनौतियां -**

इस ३४ साल पुरानी शिक्षा पद्धति के कारण शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की मानसिकता में परिवर्तन इस नीति के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। शिक्षकों पर इस नीति को समझने तथा अमल में लाने का दबाव बढ़ेगा जिसके लिए उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग की जरूरत होगी।न्यू एजुकेशन पॉलिसी२०२० के तहत३ से६ वर्ष के बच्चों को शुरुवाती पढ़ाई देने के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र बनाने पड़ेंगे क्योंकि आंगनवाड़ी की समर्थता बेहद कम होती है। इस नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक ज्ञान को भी शामिल किया गया है।

इस नई शिक्षा नीति को आत्मसात्करण करने में समय लग सकता है। इसके प्रयासों में बड़े समय तथा साधनों की आवश्यकता होगी।

इस नई शिक्षा नीति को कारगर बनाने के लिए अनुभवी तथा क्रियात्मक शिक्षकों की आवश्यकता होगी जिन की भर्ती की गुणवत्ता को पहचानना एक मुख्य काम तथा चुनौती होगी।

न्यू एजुकेशन पॉलिसी२०२० में विद्यार्थियों को तकनीकी सक्षमता प्रदान करने का प्रावधान है लेकिन जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनके लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होगी।

- **निष्कर्ष -**

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी२०२० के बारे में विस्तार से बताया है। आशा है यह नई शिक्षा नीति२०२० भारत के शिक्षा प्रणाली को और भी आसान और बेहतर बनाने में मददकरे।भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति२०२० गुणवत्ता, आकर्षण, वहनीयता में सुधार के लिए अभिनव नीतियां बनाकर और निजी क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा को खोलकर आपूर्ति में वृद्धि करके और साथ ही साथ प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त नियंत्रण के साथ इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

- **संदर्भ -**

- भारत सरकार, २०२०, नई शिक्षा नीति-२०२०, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली।
- भारत सरकार, १९८६, नई शिक्षा नीति-२०२०, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली
- भारत सरकार, १९६८, नई शिक्षा नीति-२०२०, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति२०२०: एक सिंहावलोकन,महात्मा गांधी आंतराष्ट्रीय हिंदी विश्वविध्यालय वर्धा, महाराष्ट्र।

-----------------------------*****-----------------------------